ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of the Press Briefing **12 November, 2020**

Shri P Chidambaram, Senior Spokesperson, AICC and Shri Jairam Ramesh, former Union Minister addressed the media via Video conferencing today.

Shri P. Chidambaram said- Good Evening Friends of the Media.

For the first time since data was recorded methodically — some say for the first time in the history of independent India — the Indian economy has gone into a recession, as defined by economists. In Q2 of 2020-21, according to the RBI, the quarterly economic growth rate is expected to decline by -8.6 per cent. A negative growth rate in two successive quarters is a recession.

Since these rates are calculated y-o-y, it must be remembered that in Q1 of 2019-20, the growth rate was 5.2 per cent and in Q1 of 2020-21 it was -23.9 per cent. Similarly, in Q2 of 2019-2O, the growth rate was 4.4 per cent and in Q2 of 2020-21 it is expected to be -8.6 per cent.

There is nothing to be pleased about these rates. These rates mean that we are still unable to catch up with even the tepid growth rates recorded in 2019-20. I am afraid the remaining quarters of 2020-21 will also record negative growth rates.

It is therefore surprising that the Finance Minister should quote the RBI as predicting that the economy will register a positive growth rate in the third quarter. Nearly 1 1/2 months of the third quarter is already over and there are no signs that the growth rate will turn positive in the third quarter.

The Congress party has repeatedly emphasized the steps that need to be taken to revive the economy. Let me list four of them:

1. Farmers must get fair and remunerative prices for their produce. Only a small fraction gets MSP. The recent farm Bills have put even that in jeopardy. Government has done nothing to ensure that farmers get fair prices.

2. The very poor are outside the formal economy. There are millions who have lost their jobs and livelihoods. Unless money is put in their hands, they will not be able to contribute to the revival of demand and the consequent revival of the economy. It is absolutely necessary that a scheme like NYAY must be implemented.

3. As far as the formal economy is concerned, the government has done nothing to bring back the jobs that were lost or to create new jobs. The unemployment rate on
11-11-2020 stood at 6.4 per cent.

4. It is feared that state governments will cut their capital expenditure by nearly Rs 2.7 lakh crore. That is about one-half of the budgeted capital expenditure by the states. The Centre is starving the state governments of funds and doling out measly sums of money. Unless more money is devolved on the states, the states will curtail capital expenditure in 2020-21 and the revival of the economy this year will be a pious wish.

There was more bad news yesterday and today. After demonetisation, the infant mortality rate increased to 2.9 per cent in 2017 and further to 3.1 per cent in 2018. Demonetisation affected all, except the conscience of the central government, but the most affected seem to have been infant children.

Another piece of bad news was that inequality continues to increase. The top 1 per cent of the population captured 21 per cent of the National income in 2019.

The economy continues to be in dire straits and the government does not have a plan to revive the economy. On the other hand it is busy deflecting the attention of the people from the economy and managing the headlines about the economy.

I request Mr Jairam Ramesh to add to my statement.

श्री जयराम रमेश ने कहा कि साथियों, आज हमारे देश के सामने, आज सुबह-सुबह हकीकत जनता के सामने देखने को मिली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार अगर आप तिमाही आंकड़े के अनुसार अर्थव्यवस्था का मापदंड लेते हैं, तो पहली बार जीडीपी वृद्धि दर घट नहीं रही है, बल्कि पहली बार जीडीपी खुद घट रही है। दो तिमाही, यानि के इस वित्तीय साल के 6 महीने में जीडीपी वृद्धि दर

घटी नहीं है, जीडीपी खुद घटी है, सकल घरेलू उत्पाद घटा है। वृद्धि दर घटना एक बात है, पर जीडीपी खुद घटना एक अलग बात है। तो पहली बार रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मेरे शब्द नहीं है, ये रिजर्व बैंक के शब्द हैं, एक औपचारिक वक्तव्य है, उनके एक अध्ययन के अनुसार यह कहा गया है कि पहली बार भारत में तिमाही आंकड़े के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था यानि कि इंडियन इकॉनमी रिसेशन में हैं, जीडीपी घट रही है और ये बहुत चिंता की बात है।

इसके साथ-साथ इस गंभीर समाचार को छुपाने के लिए, हैडलाइन मैनेजमेंट के लिए एक और धूम-धमाका, 'आत्मनिर्भर 3.0' की आज वित्त मंत्री ने घोषणा की है। इसका क्या असर होगा? वक्त ही बता पाएगा। बहुत से आंकड़े दिए गए हैं पर असली बात जो ये है कि 2020-21, ये पूरा वित्तीय साल एक गुजरा साल हो गया है। ये इस साल जीडीपी वृद्धि दर घटेगी नहीं, जीडीपी खुद घटेगी और अगले साल यानि के 2021-22 में क्या होगा, अभी अनुमान लगाना मैं समझता हूँ, अभी वक्त है। हम उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक रुझान सामने देखने में आएं। पर आज के हालात जो हैं, मैं समझता हूँ, चिंता का विषय है, कोई विश्वास नहीं दिलाता कि अर्थव्यवस्था में कोई जल्द से जल्द सुधार आने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति और नाजुक होने वाली है।

तीन दिन पहले 15वीं वित्तीय आयोग, फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश की है और जो हमें जानकारी मिली है कि इस रिपोर्ट की सिफारिश, जब पार्लियामेंट में पेश होगा, अगले साल बजट के संदर्भ में, राज्यों की वित्तीय स्थिति पर इसका बहुत नकारात्मक असर होगा और अगर राज्यों की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगा, मैं समझता हूँ, हमारी अर्थव्यवस्था में कोई सुधार आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप कितनी भी घोषणाएं करते जाइए पर राज्यों की वित्तीय स्थिति में अगर आप सुधार नहीं लाएंगे और उसमें केन्द्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर वो आप जिम्मेदारी से भागने वाले हैं, जैसा कि ये सरकार पिछले एक साल से कर रही है, मैं समझता हूँ कि आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

जो घोषणाएं की गई हैं आज, बहुत मोटी-मोटी घोषणाएं की गई हैं। जैसा कि मैंने कहा उद्योग पर, व्यापार पर, खासतौर से लघु एमएसएमई क्षेत्र पर इसका क्या असर होगा ,ये वक्त ही बता पाएगा, पर ये एक प्रयास किया गया आज वित्त मंत्री के द्वारा, जो रिजर्व बैंक का जो विश्लेषण था इस साल के बारे में, रिसेशन के बारे में, आर्थिक मंदी के बारे में, उसको दबाने के लिए एक बहुत बड़ा दिवाली धमाका 'आत्मनिर्भर 3.0' पैकेज जनता के सामने रखा गया। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2020-21 तो साल चला गया, अगले साल क्या होगा, वक्त ही बता पाएगा, आज हम नहीं कह सकते, पर जो मूल समस्याएं हैं, किसान से संबंधित समस्या, एमएसएमई से भी संबंधित समस्याएं और खासतौर से राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित समस्याओं पर मैं समझता हूँ केन्द्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है और इसका नतीजा और भी गंभीर पड़ेगा हमारे देश को।

एक प्रश्न पर कि सरकार ने जो आप कह रहे हैं, आत्मनिर्भर पैकेज जो आज अनाउंस किया उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार के दावों को अगर आप खारिज कर रहे हैं, तो आप किस बात को आधार मान रहे हैं, श्री जयराम रमेश ने कहा कि पैकेज घोषणा करना एक बात है। पैकेज का इंप्लीमेंटेशन, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, वो अलग बात है। ये बात सही है कि कई औद्योगिक क्षेत्रों में प्रोत्साहन की ज़रुरत थी, मांग थी, पिछले 3-4 महीने से मांग हो रही थी, सरकार चुप थी, अचानक आज क्योंकि रिजर्व बैंक ने रिसेशन की बात की है, अचानक कुंभकरण के माफिक नींद से उठकर एक 'आत्मनिर्भर 3.0' पैकेज की घोषणा की है। मैं समझता हूँ इस पैकेज के जो कई मुद्दे हैं, ये 3-4 महीने पहले किए जाने की आवश्यकता थी और बड़ी-बड़ी बातें, राज्यों से संबंधित बातें, उन पर तो ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है।

On a question that what is the Congress Party's reaction on the recent performance of the Congress in Bihar, Shri Chidambaram said- I agree, we are disappointed with the performance in Bihar and I am sure the Congress Working Committee will review the situation in Bihar and come up with a official statement of our position. But, please remember, Bihar is the poorest state of India. Mr. Narendra Modi has been Prime Minister since 2014 and Mr. Nitish Kumar has been Chief Minister since 2005, yet Bihar is the poorest state of India. In the poorest state of India, as I agree in the alternative analysis voted for no change in the Government. Well, they came pretty close to change in the Government, I think, 10 seats are this way or that way would have changed the Government. They have come pretty close to change in the Government, in fact the vote difference is 0.3%. In terms of the popular vote between NDA and Mahagathbandhan, the difference is 0.3%. They came close, they did not change the Government. We accept the verdict; we are disappointed with our performance. The CWC will review it in due course.

Sd/-
(Dr Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt.
AICC